



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, बुधवार 17 अगस्त 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 318

महत्वपूर्ण एवं खास

अमरनाथ झूठी से लौट रहे आइटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी, आधा दर्जन जवान शहीद, 30 से अधिक जवान घायल

श्रीनगर। स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में बड़ी हादसा हुआ है। आइटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस चंदनवाड़ी इलाके में खाई में गिर गई। हादसे में 6 जवानों की मौत हो गई है और 30 घायल हैं जिनमें कई की हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर स्थित आर्मी हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश हो रही है जिसके कारण पहाड़ी मार्गों में भूस्खलन एवं चट्टानों का गिरना लगातार देखा जा रहा है। होना हो इस बड़े घटना का कारण यह भी हो सकता है।

मुंबई की एंटी नॉरकोटिक्स सेल ने की बड़ी कार्यवाही, जब्त की 516 किलो ड्रग्स

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए 516 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1026 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्यवाही ऐसे समय में हुई, जब कुछ ही दिन पहले मुंबई पुलिस की एंटी नॉरकोटिक्स सेल (एएनसी) ने गुजरात की सीमा से लगे पालघर जिले के नाला सोपारा कस्बे से 1,403 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में ड्रग्स बरामदगी की थी। बता दें कि एएनसी ने 3 अगस्त की रात नाला सोपारा के चक्रधर नगर क्षेत्र में सीताराम बिल्डिंग से एक व्यक्ति को 702 किलोग्राम मेफेडोन के साथ पकड़ा और दो पेडलर को गिरफ्तार किया था। जब्त ड्रग्स की कीमत 1,403.5 करोड़ रुपये बताई गई थी। ड्रग्स की बरामदगी दो अन्य ड्रग्स डीलर्स और एक महिला से पूछताछ के बाद संभव हुई, जिन्हें एएनसी ने 29 मार्च को उतर-पूर्वी मुंबई के गोवंडी से पकड़ा था। गिरफ्तारी तीनों में से एक को 250 ग्राम मेफेडोन, जिसकी कीमत 37.50 लाख रुपये और दूसरे को 2.70 किलोग्राम मेफेडोन के साथ, (जिसकी कीमत 4.14 करोड़ रुपये है) पकड़ा गया था।

पति से मारपीट के बाद महिला ने 3 बेटियों को दिया जहर

गाजीपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक चौकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक महिला ने अपने पति के साथ विवाद के बाद अपनी तीन बेटियों को जहर दे दिया। घटना सुहवाल थाना क्षेत्र के भनमाल राय गांव की है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, महिला का कथित तौर पर पति से घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और इसके बाद उसने अपनी तीन बेटियों को जहर दे दिया। दो बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरी बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जो अब पुलिस हिरासत में है। तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

ट्रक और इनोवा में हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 घायल

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम में मंगलवार तड़के 1.40 बजे एक ट्रक के पलट जाने और इनोवा कार से टकरा जाने से दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-48) पर सिधरावली गांव के पास कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के अनुसार हादसे में 1 महिला और 3 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब चालक समेत छह लोग इनोवा कार से उदयपुर से नोएडा जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि, मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि सभी मृतक नोएडा में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। बिलासपुर पुलिस थाने के थाना प्रभारी निरीक्षक अजय मलिक ने कहा, हमने मृतक के परिवारों और घायलों को सूचित कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही जारी है।

गांधी जयंती से शुरू होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, एक वर्ष में 300 पार्क की स्थापना का लक्ष्य

- न्याय की विरासत के साथ आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़: भूपेश
- मुख्यमंत्री ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण
- जन्माष्टमी से 'कृष्ण कुंज योजना' की होगी शुरुआत
- छत्तीसगढ़ में 5.03 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित
- पेसा कानून में ग्राम सभाओं को मिलेगा जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार
- आगामी शिक्षा सत्र में 422 स्कूलों में लागू होगी स्वामी आत्मानंद योजना

के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। प्रकृति-सम्मत विकास की राह पर आगे बढ़ा छत्तीसगढ़- मुख्यमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामों का उल्लेख करते हुए कहा था- 'भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे अभी शहरों और कस्बों से भिन्न अपने सात लाख गांवों के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है।' आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कृषि व वन भूमि का काम होना, पर्यावरण अस्तंतुलन, प्रदूषण, बीमारियों, महंगाई, बेरोजगारी आदि से लोगों का जीवन संकटमय हुआ है। हमने पुरखों की सीख और माटी की संस्कृति का सम्मान करते हुए कृषि तथा वन उत्पादों, परंपरागत ज्ञान, आधुनिक साधनों व रणनीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। मुझे गर्व है कि हम आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने, बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति-सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं।



देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। 'गोधन न्याय योजना' भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठानों में निर्मित जैविक खाद, अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। किसानों की सिंचाई कर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों को 342 करोड़ रुपए की राशि माफ की जा चुकी है। किसानों को 4 वर्ष पहले मात्र 3 हजार 692 करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था। हमने इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 6 हजार 500 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे लगभग 75 प्रतिशत अधिक राशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र में आएगी। 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तहत अब-तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।

प्रदेश में 35 हजार से अधिक कृषि पंपों का ऊर्जाकरण- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी, उसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। यही वजह है कि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सौजन्य में किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की आदान सहायता देने वाला

छत्तीसगढ़ में खेती बर्नी लाभ का जरिया- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खेती को लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए, इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21 लाख 77 हजार से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12 लाख 6 हजार थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9 लाख 71 हजार बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण अनाज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ न सिर्फ स्वावलम्बी हुआ है बल्कि प्रदेश में कुल आवश्यकता का 270 प्रतिशत अधिक अनाज उत्पादन हुआ है। फसल विविधीकरण की गति बढ़ाने के लिए 'टी-कोफी बोर्ड' का गठन किया गया है। दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। इस वर्ष से दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। खरीफ 2021 में धान के बदले 17 हजार 539 एकड़ क्षेत्र में दलहन, तिलहन एवं 240 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है। रबी योजना 2021-22 में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा 95 हजार हेक्टेयर कम करते हुए 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का एवं शोध रकबे में दलहन, तिलहन, साग-सब्जी की फसलें लगाई गई हैं। खरीफ 2022 में धान के 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को दलहन-तिलहन एवं अन्य उद्योगिक फसलों से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

लघु धान्य फसलों को प्रोत्साहन- प्रदेश में लघु धान्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन' का गठन किया गया है। कोदो, कुटकी, रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर

इनकी खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। **नरवा योजना: भू-जल स्तर में 30 प्रतिशत तक वृद्धि-** मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सुराजी गांव योजना' से छत्तीसगढ़ को स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने, भू-जल संरक्षण व रिचार्जिंग को बढ़ाने और कृषि भूमि को जहरीले रसायनों से मुक्ति दिलाने हुए जैविक खेती में मदद मिल रही है। 'नरवा योजना' से विभिन्न नालों में 99 लाख रुपए से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे उपचारित क्षेत्र में भू-जल स्तर में 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, वहीं नालों में पानी की उपलब्धता भी दो माह अधिक रहने लगी है। 'गुरुवा योजना' में पहले हमने गौठानों के विकास पर जोर दिया। अब-तक 8 हजार 408 गौठानों को विकसित किया जा चुका है, जो 'रोका-छेका अभियान' के साथ आर्थिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र बने हैं। गोबर से बिजली बनाने के लिए 'भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर' के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु एमओयू किया गया है। गोबर से ऑयल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा रही है।

गांधी जयंती से 'रूरल इंडस्ट्रियल पार्क' की होगी शुरुआत- मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को आजीविका-केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु हम 'ग्रामीण आजीविका पार्क' अर्थात् 'रूरल इंडस्ट्रियल पार्क' प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती अर्थात् 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारम्भ किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गो-मूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर

दी है, जो 'रासायनिक पेस्टिसाइड्स' के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। 'बाड़ी योजना' अंतर्गत प्रति गौठान एक से डेढ़ एकड़ तक भूमि चिह्नान्कित की गई है और अभी तक 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी हैं। राज्य के बम्पर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरी होने के बाद, शेष धान से 'बायो एथेनॉल' के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 निवेशकों के साथ एमओयू भी किया है। विकासखण्डों में फूडपार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिह्नान्कित की जा चुकी है और इनमें से 52 विकासखण्डों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया गया है। परम्परागत कौशल के वैल्यू-एडिशन के लिए हमने 'सी-मार्ट' की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्व-सहायता समूहों के सामर्थ्य उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। **मनरेगा में 2,709 अमृत सरोवर निर्मित-** श्री बघेल ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा कि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन-यापन करने वाले परिवारों की जीवन-रखा-मानने हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2021-22 में हमने 'लेबर बजट' के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108 प्रतिशत अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था, हमने उससे अधिक 8 हजार 709 अमृत सरोवर निर्मित किए। गौठानों के निकट मछली पालन के 1 हजार 859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1 हजार 318 पूर्ण कर दिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है।

भारतीय सेना की ताकत में बढ़ोतरी, राजनाथ सिंह ने 'निपुण' समेत सौंपे कई स्वदेशी हथियार

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंप कर सेना की ताकत बढ़ाई। इन हथियारों में एंटी-कार्मिक लैंड माइन निपुण, पैगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इन हथियारों में एंटी पर्सनल माइंस, आमने सामने लड़ाई के हथियार, इन्फैंट्री के लड़ाकू वाहन शामिल हैं।



देश की सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कई स्वदेशी हथियार सेना को सौंपे। इनमें एके-203 और एफ-इंसास राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन 'निपुण' भी शामिल है। नए हथियार ईईएल व अन्य और एके-203 अर्साएल राइफल व शस्त्रों की जानकारी दी गई।

इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सेना प्रमुख की ओर से देश को आश्चर्य किया है कि हम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं। भले वह पश्चिमी रेगिस्तान (पाकिस्तान) हो या लड़ाकू सेक्टर में ऊंचाई वाले स्थान (चीन) से सटे इलाके। यह बात उन्होंने सेना को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां सौंपे जाने के दौरान कही। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री सोल्यूशन इन एडिस्टम (एफ-इंसास) की नई हथियार प्रणालियों और एके-203 अर्साएल राइफल व शस्त्रों की जानकारी दी गई।

कश्मीरी हिंदू पर आतंकियों ने फिर किया कातिलाना हमला

कश्मीर। स्वतंत्रता के 75 साल का जश्न मना रहे देश में मंगलवार को बुरी खबर आई। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर गोलियां चला दीं। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। कश्मीर जोन पुलिस ने घटना की जानकारी दी है। शुक्रवार को ही दहशतवादी ने बंदीपोरा में बिहार के रहने वाले मोहम्मद अमरेज की हत्या कर दी थी। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी कि आतंकवादियों ने शोपियां में चोटीपोरा स्थित एप्पल ऑर्चर्ड में गोलीबारी कर दी। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षाबल भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। खबर है कि पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। मृतक का नाम सुनील कुमार भट्ट है और भाई का नाम पितू कुमार बताया जा रहा है।



जम्मू-कश्मीर में सोमवार को आतंकवादियों के दो ग्रेनेड हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के एक नागरिक सहित दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने एक घंटे के भीतर दो ग्रेनेड हमले किए। उन्होंने बताया कि पहला हमला बडगाम जिले के चट्टा में अल्पसंख्यक बस्ती में किया गया, जबकि दूसरा हमला श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष पर। शुक्रवार को बंदीपोरा जिले में आतंकवादियों ने बिहार के मजदूर अमरेज की हत्या कर दी थी। घटना के बाद व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले पुनवावामा के गड्डा गांव में भी आतंकियों ने बिहार के मजदूर का कत्ल कर दिया था। घायल की पहचान मोहम्मद मुताज के रूप में हुई थी।

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री बना मुख्य केन्द्र

नई दिल्ली। आजादी के बाद भारत के सामने चुनौतियां तो अनेक आईं लेकिन उन्हें पीछे छोड़ते हुए इसने दुनिया में अपना जो श्रेष्ठ स्थान बनाया है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। देश आजाद हुआ तब देशवासियों के सामने खाने-पीने-पहनने का संकट था, क्योंकि तब हम इन सबके लिए आयात पर निर्भर थे। लेकिन 75 वर्षों के बाद आज हम दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। साढ़े सात दशक में देश ने कई युद्ध लड़े, मंदी का साया कई बार गहराया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अटल रही। आज भी जब अमेरिका और यूरोप के फिर मंदी में पड़ने पर दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। दुनिया के तमाम देशों को भारत सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगा। अंग्रेजी शासन से तुलना करें तो आजादी से पहले



50 वर्षों तक भारत की औसत विकास दर सिर्फ 0.75 प्रतिशत थी। देश की कूट उपलब्धियां देखिए। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस के अनुसार 1950-51 से 2020-21 तक प्रति व्यक्ति आय 7114 रुपये से (स्थिर मूल्यों पर) 12 गुना बढ़कर 85110 रुपये हो गई। अनाज उत्पादन 508 लाख टन से छह गुना बढ़कर 3086 लाख टन पहुंच गया। तब बिजली उत्पादन 5 अरब किलोवाट का होता था, यह 275 गुना बढ़कर 1373 किलोवाट हो गया है। निर्यात में 3562 गुना की वृद्धि हुई है। 1950-51 में सिर्फ 608 करोड़ रुपये

का निर्यात हुआ था, जबकि 2020-21 में 29.16 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इस दौरान देश की आबादी भी 36 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हुई है। भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की छठी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहां का 47 लाख करोड़ रुपये का रिटेल मार्केट दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है। कारों की बिक्री के मामले में चीन, अमेरिका और जापान के बाद भारत सबसे बड़े जेनेरिक ड्रग उत्पादक हैं, बल्कि सबसे बड़े वैक्सिन निर्माता भी हैं। इसलिए भारत को दुनिया की फार्मसी भी कहा जाता है। यूजर संख्या के लिहाज से यहां की टेलीकॉम इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे

नंबर पर पहुंच गई है। इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम, गारमेंट, आईटी आदि जैसे सेक्टर में भारत बड़ा निर्यातक भी बन गया है। भारत ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का आधार तो है ही, आज देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और इस मामले में यह तीसरे नंबर पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत भी स्वर्णिम रहा है। वर्ष 1700 के आसपास विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा एक चौथाई था और यह समूचे यूरोप के बराबर था। ग्लोबल मैयूफेक्चरिंग में भी भारत लगभग इतना ही योगदान करता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योग बंद होने से वर्ष 1900 में भारत का औद्योगिक उत्पादन दुनिया का सिर्फ दो फीसदी रह गया। आजादी के समय दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा सिर्फ चार

फीसदी था। हालांकि अब भी यह 3.2ल है, लेकिन अब विश्व अर्थव्यवस्था काफ ी बड़ी हो गई है। आर्थिक सुधारों से पहले 1991 में वह समय भी आया जब भारत की इकोनॉमी 17वें स्थान पर पहुंच गई थी। तब विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 5.8 अरब डॉलर का रह गया था, अब 573 अरब डॉलर का है। भारत की विकास दर 1950 के दशक में ही आजादी से पहले की तुलना में पांच गुना हो गई थी। इसका एक कारण यह था कि पहले हमारे देश की बजट बाहर चली जाती थी और यहां निवेश नहीं हो पाता था। आजादी के बाद देश में ही निवेश होने लगा। संसाधन कम थे, सो उनका बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी था। इसलिए योजना आयोग बना, उद्योग और कृषि नीति बनी।